

राकरा रामो,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

या मे,
समस्त प्रमुख सचिव, / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विभाग
विषय- राज्याधीन सेवाओं शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिव्य ज्ञान के सम्बन्ध में।

होदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं / सार्वजनिक उद्यमों / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल रूप में विद्यमान वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आँकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रिजिड सर्वे) आँकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है -

| | |
|----------------------|-----|
| (1) अनुसूचित जाति | 19% |
| (2) अनुसूचित जनजाति | 04% |
| (3) अन्य पिछड़ा वर्ग | 14% |

2- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, मृतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम

युद्धों के आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय -

| | |
|---|-----|
| (i) महिलाएं | 20% |
| (ii) मृतपूर्व सैनिक | 02% |
| (iii) विकलांग व्यक्ति | 03% |
| (iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित | 02% |

जो महिला / व्यक्ति निम्न वर्ग की होगी / होगा, उसी वर्ग में हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3- आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय

(राजेश शर्मा)

सचिव

(127)

PRINCIPAL
Dr. P.D.B.H. Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2019

विषय- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र-छात्राओं को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49) की धारा-32 (1) व (2) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है-

- 32.(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five percent seats for persons with benchmark disabilities.
- (2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्रख्यापित उक्त धारा-32 (1) व (2) के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

अतएव कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 33 (1)/XXIV(4)/2019-25(01)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

PRINCIPAL
Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

आज्ञा से,

(डॉ० अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आनन्द बर्द्दैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 जुलाई, 2019

विषय- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-विधि/2699/अन्य-45/2019, दिनांक 05 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.20013/01/2018-BC-II, दिनांक 17 जनवरी, 2019 (संलग्नक-1) द्वारा उक्तानुसार अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि विद्यार्थी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-64/XXXVI (3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 (संलग्नक-2) द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को जिन पर भर्ती की जानी है, दस प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना में कतिपय अन्य दिशा-निर्देश एवं प्राविधान भी किये गये हैं।

3- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्राविधानों एवं विभिन्न दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु प्रत्येक शाखा में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने की स्वीकृति इस प्रकार प्रदान की जाती है कि छात्रों के लिए सीटों की कुल संख्या में वृद्धि की जायेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बाद, संख्या या सीटें पूर्ववर्ती एकेडमिक सत्र की तरह ही रहे।

4- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।



भवदीय,

(आनन्द बर्द्दैन)
प्रमुख सचिव।

PRINCIPAL

Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

संख्या- 1022-(1)/XXIV(4)/2019-01(03)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव/प्रमारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल द्वारा-प्रमारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-प्रमारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड द्वारा-प्रमारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।
11. एन.आई.सी (निदेशक), सचिवालय परिवार, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)

अपर सचिव।

PRINCIPAL

Dr. P.D.B.H. Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

F. No.20013/01/2018-BC-II

Government of India

Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment

17th January, 2019

Shastri Bhawan, New Delhi

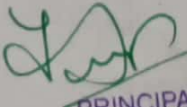
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.


In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

- i. 5 acres of Agricultural Land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;


PRINCIPAL
Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

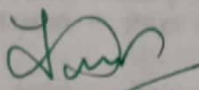
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/ UT.
4. Every Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority, increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, are not less than the total seats available in the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.
5. Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DoPT and Ministry of HRD respectively.


(B.L. Meena)

Joint Secretary to the Government of India

To

1. The Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi
2. The Secretary, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi


PRINCIPAL
Dr.P.D.B.H. Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)



F No: 12-4/2019-U1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 17 January, 2019


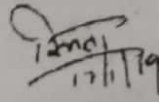
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) for admission in Central Educational Institutions.

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, it has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten per cent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

- a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institutions, (as defined in clause (d) of section (2) of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.
- b) The above reservation would not be applicable to the 8 institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.
- c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of

PRINCIPAL
Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)

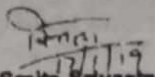
study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

- d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.
- e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

4. This issue with the approval of the Minister for Human Resource Development.

Encl: As above


(Smita Srivastava)
Director

1. Chairman UGC
2. Chairman AICTE
3. Chairperson NCTE
4. All Bureau Heads of Department of Higher Education

Copy to:

Chief Secretaries of all State Governments/UTs: with a request to give effect to the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 for all higher educational institutions funded/aided, directly or indirectly, by the State Government in such manner that the provision for reservation for EWS would become operational from the academic year 2019-20.



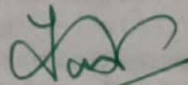
PRINCIPAL
Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Koldwar (Garhwal)

SCHEDULE

(The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006)

S.No. Names of the Institutions of Excellence, etc.

1. Homi Bhabha National Institute, Mumbai and its constituent units, namely:-
 - (i) Bhabha Atomic Research Centre, Trombay;
 - (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam;
 - (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore;
 - (iv) Institute for Plasma Research, Gandhinagar;
 - (v) Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata;
 - (vi) Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;
 - (vii) Institute of Physics, Bhubaneswar;
 - (viii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai;
 - (ix) Harish-Chandra Research Institute, Allahabad;
 - (x) Tata Memorial Centre, Mumbai.
2. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Shillong.
4. National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon.
5. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
6. Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
7. Space Physics Laboratory, Thiruvananthapuram.
8. Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.



12/1/19

— PRINCIPAL —

Dr.P.D.B.H.Government Post Graduate College
Kotdwar (Garhwal)